

न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बर्डजलास प्रियंका गोस्वामी आर०ए०एस० अति० संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 80/2008/अपील/एल.आर.एक्ट/बारा
दायरा दिनांक: 20.6.2008
अन्तर्गत धारा: 75 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

- 1 लक्ष्मी चंद उर्फ लक्ष्मीनारायण आत्मज कस्तूर चंद जाति माली निवासी ग्राम सरकन्या तहसील अन्ता जिला बारा (राज०)।

...अपीलांत

बनाम

- 1 मृतक हीरालाल आत्मज मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम सरकन्या तहसील अन्ता जिला बारां जरिये कायम मुकामान:-
1/1-छीतरलाल आत्मज स्व० हीरालाल
1/2-रामदेव आत्मज स्व० हीरालाल
1/3-हेमराज आत्मज स्व हीरालाल
जाति माली निवासी ग्राम सरकन्या तहसील अन्ता जिला बारां
1/4-शांतिबाई पुत्री स्व० हीरालाल पत्नी रामकल्याण निवासी डाबरी काका जी
1/5-कांति बाई पुत्री स्व० हीरालाल पत्नी रामप्रसाद निवासी ग्राम बडगांव तहसील अन्ता जिला बारां।
1/6-द्रोपदी बाई पुत्री स्व० हीरालाल पत्नी घनश्याम निवासी तेल फेक्ट्री बारा जिला बारा।
1/7-कमला बाई पुत्री स्व० हीरालाल पत्नी नामालूम जाति माली निवासी रायथल तह० मांगरोल जिला बारा।
1/8-मांगीबाई विधवा हीरालाल पत्नी घनश्याम जाति माली निवासी ग्राम सरकन्या तहसील अन्ता जिला बारा।
2 छीतरलाल आत्मज हीरालाल जाति माली निवासी ग्राम सरकन्या तहसील अन्ता जिला बारा।
3 राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा।

...रेस्पोजेन्ट



उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
श्री जगदीश नन्दवाना अभिभाषक रेस्पोजेन्ट

...निर्णय...

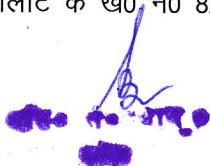
दिनांक 30.1.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं० 68/02 प्रा० पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान हीरालाल, छीतरलाल बनाम राज० सरकार जरिये तह० अन्ता व लक्ष्मीचंद मे पारित निर्णय दिनांक 13.5.2008 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 मे न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

- 1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि हीरालाल, छीतरलाल द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र उप खण्ड अधिकारी मांगरोल के यहां इस आशय का पेश किया कि ग्राम सरकन्या मे ख० नं० 750/216 रकबा 4 बीघा तथा ख० नं० 752/217 रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा कुल 33 बीघा 19 बिस्वा भूमि उसने खाते तथा लक्ष्मीचंद उर्फ लक्ष्मीनारायण के पिता कस्तूरचंद, पन्नालाल की खातेदारी मे ख० नं० 449/216 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज थी। बन्दोबस्त सं० 2015-24 मे ख० नं० 750/216, 752/217 का रकबा 32 बीघा 6 बिस्वा ख० नं० 379 से दर्ज किया गया। इस प्रकार उसके खाते मे 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि कम कर दी गई। इसके विपरीत लक्ष्मीचंद की भूमि ख० नं० 749/216 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर ख० नं० 381 दर्ज कर 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज की

गई इस प्रकार लक्ष्मीचंद के खाते मे 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज की गई। वर्तमान बन्दोबस्त से पूर्व 16 बीघा 14 बिस्वा भूमि उसकी नहर मे चली गई इसके बाद रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा होना चाहिये लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा हाल ख0 नं0 820, 821, 823, 824, व 825 कायम कर रकबा 2.28 है0 दर्ज किया गया जो गत रकबे की तुलना मे 0.64 है0 कम दर्ज किया गया। लक्ष्मीचंद की भूमि के नये ख0 नं0 826 रकबा 1.85 है0 दर्ज किये जो गत के मुकाबले अधिक दर्ज की गई जबकि ख0 नं0 822 की 4 बीघा भूमि प्रार्थी ही काशत कर रहे है अतः रकबा सही किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लक्ष्मीचन्द के खो की आराजी ख0 नं0 826 रकबा 1.85 है0 मे से 0.64 है0 भूमि कम कर हीरालाल वगेरा के खाते दर्ज करने व लक्ष्मीचंद के खाते मे ख0 नं0 826 रकबा 1.21 है0 भूमि तथा हीरालाल वगेरा के खाते मे 1.83 है0 के स्थान पर 2.47 है0 भूमि दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने का दिनांक 13.5.08 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे अपील कर निवेदन किया कि अपीलांट के 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि सही रूप से दर्ज की गई थी रेस्पो0 की भूमि अपीलांट के खाते दर्ज नहीं की गई थी तथा ना ही अपीलांट व रेस्पो0 की भूमि पास-पास है इस तथ्य को रेस्पो0 1 व 2 द्वारा प्रमाणित भी नहीं किया गया था इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 नं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर जेरअपील आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है। सम्वत 2015 के भू प्रबन्ध की त्रुटि को 40-50 वर्ष पश्चात धारा 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र के आधार पर दुरुस्त नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति मे रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट पोषणीय नहीं था। ख0 नं0 826 की सम्पूर्ण 1.85 है0 भूमि पर अपीलांट काबिज काशत रहा है धारा 136 एलआरएक्ट मे केवल लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकारान की सहमति के आधार पर राजस्व अभिलेख मे हुई त्रुटि को दुरुस्त किया जा सकता है। अपीलांट ने उक्त प्रकरण को कस्टेस्ट किया था ऐसी स्थिति मे उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये रेस्पो0 को कानूनन कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता इस कानूनी बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने गोर किये बिना जेरअपील आदेश पारित कर त्रुटि की है। तह0 अन्ता द्वारा मौके की स्थिति की एक पक्षीय तैयार की गई रिपोर्ट अवैध, त्रुटिपूर्ण एवं मनमानी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत धारा 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। बार-बार पत्र/स्मरण पत्र/अ0 शा0 पत्र लिखे जाने उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय से जेरअपील आदेश से संबधित वांछित अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ। अपील प्रकरण न्यायालय हाजा मे वर्ष 2008 से अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय मे लम्बित होने व वांछित अभिलेख प्राप्त नहीं होने पर अभिभाषक उभय पक्षकार द्वारा प्रकरण से संबधित दस्तावेजात प्रस्तुत करते हुये पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड/दस्तावेजात के आधार पर अपील का निर्णय करने की सहमति प्रकट किये जाने पर अपील प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुये जाहिर किया सेटलमेंट विभाग की भूमि सही रूप से दर्ज की गई है जिस पर अपीलांट काबिज काशत है। रेस्पो0 की भूमि अपीलांट के आस-पास नहीं है ना ही रेस्पो0 की भूमि अपीलांट के खाते मे दर्ज की गई। सं0 2015 के सेटलेमेंट के आधार पर दर्ज भूमि को 40-50 वर्ष बाद धारा 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र के आधार पर दुरुस्त नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं था। धारा 136 एलआरएक्ट मे केवल लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकारान की सहमति के आधार पर राजस्व अभिलेख मे हुई त्रुटि को दुरुस्त किया जा सकता है। अपीलांट ने उक्त प्रकरण को कस्टेस्ट किया था ऐसी स्थिति मे उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये रेस्पो0 को कानूनन कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता इस कानूनी बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने गोर नहीं कर तहसीलदार अन्ता द्वारा मौके की स्थिति की एक पक्षीय अवैध, त्रुटिपूर्ण एवं मनमानी तैयार की गई रिपोर्ट को आधार बनाकर जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 एलआरएक्ट निरस्त किया जावे।
- 4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय तहसीलदार अन्ता से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है। तहसीलदार रिपोर्ट एवं मिलान क्षेत्रफल सं0 2044-63 के अनुसार अपीलांट के ख0 नं0 826 रकबा 1.85 है0 ख0 नं0 381 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा से बना है जो सही दर्ज है परन्तु



सेटलमेंट सं० 2015-24 में ख० नं० 381 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा के ख० नं० 749/216 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा दर्ज था इस प्रकार अपीलांत के खाते में गत की तुलना में 4 बीघा (0.64) है० भूमि अधिक दर्ज खाता है तथा मौका स्थिति के अनुसार ख० नं० 826 रकबा 1.21 है० भूमि पर अपीलांत तथा शेष 0.64 है० भूमि पर रेस्पो० का कब्जा काश्त होने से जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जावे।

- 5 हमने अपील एवं प्रकरण में उभय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का आध्योपांत अवलोकन कर प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो० अभिभाषक पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने हीरालाल व छीतर लाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट को निर्णय दिनांक 13.5.08 से स्वीकार कर लक्ष्मीचंद के खाते की आराजी ख० नं० 826 रकबा 1.85 है० में से 0.64 है० भूमि कम कर हीरालाल वगैरा के खाते दर्ज करने व लक्ष्मीचंद के खाते में ख० नं० 826 रकबा 1.21 है० भूमि तथा हीरालाल वगैरा के खाते में 1.83 है० के स्थान पर 2.47 है० भूमि दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांत का मुख्य तर्क है कि सं० 2015 के सेटलमेंट के आधार पर दर्ज भूमि को 40-50 वर्ष बाद धारा 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र के माध्यम से दुरुस्त नहीं किया जा सकता अतः अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं था। धारा 136 एलआरएक्ट में केवल लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकारान की सहमति के आधार पर राजस्व अभिलेख में हुई त्रुटि को दुरुस्त किया जा सकता है। अपीलांत ने उक्त प्रकरण को कस्टेस्ट किया था ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये रेस्पो० को कानूनन कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता इस कानूनी बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया इसके विपरीत विद्वान अभि० रेस्पो० का कथन है कि अपीलांत के खाते में गत की तुलना में 4 बीघा (0.64) है० भूमि अधिक दर्ज खाता होने तथा मौका स्थिति के अनुसार ख० नं० 826 रकबा 1.21 है० भूमि पर अपीलांत तथा शेष 0.64 है० भूमि पर रेस्पो० का कब्जा काश्त होने से तहसीलदार अन्ता की रिपोर्ट के आधार पर जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। उभय पक्षकारान के उपरोक्त तर्कों पर मनन करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती को विहित रीति से शुद्ध कर सकता है जिनको अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत प्रकरण को अपीलांत द्वारा कस्टेट किया है ऐसी स्थिति में 40-50 वर्ष पूर्व सेटलमेंट के दौरान हुई त्रुटि तहसीलदार अन्ता की रिपोर्ट को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट के माध्यम से दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है। प्रकरण में यह तथ्य भी विवेचनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय पारित करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल तथा बंदोबस्त के पूर्व एवं बाद के नक्शे का अवलोकन किये बिना तथा रकबा बरारी किये बगैर मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार कर जेरअपील निर्णय दिनांक 13.5.08 अपास्त किया जाकर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किये जाने योग्य है।
- 6 उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं० 68/02 प्रा० पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान हीरालाल, छीतरलाल बनाम राज० सरकार जरिये तह० अन्ता व लक्ष्मीचंद में पारित निर्णय दिनांक 13.5.2008 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में राजस्व रिकार्ड का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।
- 7 निर्णय आज दिनांक 30.1.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति० संभागीय आयुक्त

कोटा